[Shri M. M. Jacob]

they are not implementing it because of the financial constraints and deficit financing in their own respective States.

Another point associated with this is that the scheme does not cover the commercial scheduled banks which are under private sector. The reason why private sector banks have been kept outside the scope of the scheme and how they should face the situation has not been spelt out either by the Central Government or by the Reserve Bank of India. In fact, ever since the nationalisation of the banks some of these scheduled banks in my own State of Kerala—because I know them intimately—are also lending to the priority sector, particularly to the farmers and the weaker sections in pursuance of the national targets and policy directives issued by the Government from time to time.

As regards the lending policies and the other general banking regulations there should be no distinction between private and public sector banks. The private sector banks too have contributed reasonably well to the rural development and are meeting the obligations under the Service Approach Area Schemes, as it is known already. Twenty to thirty per cent of the lending programmes in my State are done through these commercial banks which are scheduled and which are run according to the guidelines and directives of the Reserve Bank of India. So a large number of farmers are always covered under these. Therefore, the situation that emerges is the exclusion of the private sector banks from the purview of the debt relief scheme will have far reaching repercussions. Already the category of borrowers of private sector banks who are otherwise qualified for debt relief schemes are tempted to default repayment of their loan and have started approaching banks for loan waiver which the public sector banks are expected to operate. It is noteworthy that even in the case of private sector banks the revenue recovery proceedings are expected to be stopped as per the directives of the Collector or the district authorities thinking that they are also covered by these. So the additional loan waiver scheme has not been benefiting the farmers. So my request is that in this particular situation something has to be done by the Finance Ministry (1) to make sure that 10% of the money is given to the cooperatives and the village credit societies because the State Governments are not implementing it, and (2) to bring into the orbit of the category the scheduled banks which are also approved by the Reserve Bank— I am not talking of the money-lenders but the scheduled commercial banks which are of a high standard, which have hundreds and hundreds of branches—since they are catering to the needs of the rural folk so that this will be a good relief to the farmers. I would request the Government to look into the matter.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय जेकब जी ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं ।

साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर एक प्रश्न और बहुत गंभीर हो गया है । कोआपरेटिव बैंक की वसूली भी बड़ी तेजी के साथ हो रही है । यहां तक की कुड़की भी आरम्भ हो गई है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को जेकब साहब ने उठाया है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और यह भी देखे कि जो दस हजार तक के को-आपरेटिव बैंक के लोन को भी माफ करने के लिए घोषणा की गई थी, उसे भी लागू करे और इसके लिए किसानों के ऊपर वसूली के लिए जो जबरदस्ती की जा रही है, उसे भी समाप्त करे और ऐसे निर्देश केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को भी जाने चाहिएं ।

Communal Riots in Gujart

श्री राम सिंह राठवा (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, गुजरात के वड़ोदरा, आनन्द और सूरत में हुए सांप्रदायिक दंगों की ओर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

देश के लिए यह बड़ी कमनसीबी की बात है कि देश गंभीर से गंभीर समस्या की ओर अकेला जा रहा है और केन्द्र सरकार एवं उसी राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें भी सिर्फ एक मूक और असहाय दृष्टी के रूप से उसे देख रहे हैं। पंजाब, कश्मीर, असम, बोड़ो, तमिल नाडू एवं मध्य-पूर्व में फसे हुए भारतीयों की नई-नई समस्यायें सामने आती रहती हैं, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल तो दूर, समस्या कम करने का भी कोई ठोस कदम या कार्यक्रम इस सरकार के पास दिखाई नहीं देते हैं।

परिणामस्वरूप, समस्याओं की तीव्रता बढ़ती जा रही है। समाज में उपस्थित अपराधी भी परिस्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। सांप्रदायिकता अपना सर बुलन्दी से उठा रही है। कल गुजरात में सांप्रदायिक ताकतों ने अपना जो तमाशा दिखाया, उससे सभी देशवासियों के सर शर्म से झुक गए हैं और दंगे सिर्फ एक नगर तक सीमित नहीं हैं, आनन्द, सूरत और दूसरे छोटे-छोटे नगरों में भी धीरे-धीरे बढ़ गए हैं। इसके साथ-साथ अंकलेश्वर और कपड़वंज में भी कल से शुरु हुआ है। यह एक गहरी साजिश का नमूना है। मतलब रिपोर्ट के अनुसार कम से कम चौदह व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कोई सौ घायल हो गए हैं। यह जानते हुए भी सांप्रदायिक ताकतों को कौन समर्थन कर रहे हैं? न ही राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार इन कट्टरतावादियों को कुछ कर सकती है, क्योंकि सभी धर्मों की जो शक्तियां सांप्रदायिकता का समर्थन करती हैं वही तत्व सरकार को भी समर्थन करते हैं। दूसरे अर्थ में, मौजूदा सरकार और सांप्रदायिकता एक-दूसरे के पर्याय बन कर रह गए हैं। अब सांप्रदायिकता के प्रयाय के पास से सांप्रदायिक समस्याओं के हल की आशा रखना भी कितना विरोधाभासी हो रहा है आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर कुछ मंडल आयोग के विरोध करने वाले जो लड़के हैं उनकी जो आवाज को नीचे दबाने के लिए गुजरात की सरकार ने अपने पुलिस वालों को सादे ड्रेस में भेज कर, वह जो लीडर हैं उनकी लीडरशीप समाप्त कर देने के लिए उनके ऊपर पिटाई भी की गई है, मेरी आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है कि इस सभा को परिस्थिति से अवगत कराने हेतु **(व्यवधान)**

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat) : Sir, I want to intervene now. I do not know how he is saying these things ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : In Special Mentions, there is no intervention. Please sit down.

श्री राम सिंह राठवा : एवं राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ कर जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही का इस सभा को सरकार से आश्वासन दिलाएं। धन्यवाद।

श्री राजूभाई ए. परमार (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, राठवा जी ने जो मसला उठाया है उसका हम समर्थन करते हैं और गुजरात में अभी जो सरकार चल रही है ... **(व्यवधान)** ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : You can only associate with it, if you want.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Sir, he has no evidence to say all those things ...(*Interruptions*)...

श्री राजूभाई ए. परमार (गुजरात) : जो लोग ... **(व्यवधान)** उसमें हमारे गृह मन्त्री जो भाड़े के गुंडे रखते हैं उनसे जो अत्याचार करवाते हैं वह बहुत ही गंभीर बात है और सरकार द्वारा स्टूडेण्ट पर अत्याचार किया गया है और उसके हाथ-पैर

[श्री राजूभाई ए. परमार]

तोड़ दिए गए हैं और इस पर हमारे गृह मन्त्री जी के रखे हुए भाड़े के लोग यह कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच की जाए और ऐसे गृह मन्त्री से, ऐसी सरकार से आप इसका जवाब मांगिए कि क्यों यह हो रहा है ?

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) : डिप्टी चेयरमैन से मेरी बात हो चुकी है और मैंने इजाजत भी ली है । सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कि कम्युनल डिस्टर्बेंसेस जो हमारे गुजरात में हो रहे हैं इसके बारे में क्या अहम वजह है इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है । मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे बड़े-बड़े टाउन में अब नहीं हो रहे हैं, छोटे-छोटे टाउन्ज, सब-टाउन्ज जो हैं वहां हो रहे हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पूरे देश का मामला है और इन सारे डिस्टर्बेंसेस को हम देखें तो यह बी. जे. पी. की पूरी साजिश है सारे हिन्दुस्तान में और उसी तरह सारे देश में यह वर्टिकल स्पलिट करना चाहती है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : कांग्रेस की साजिश है ।

श्री छोटूभाई पटेल : मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में जहां-जहां नहीं हो रहे हैं और व्यड़वन्ज में हो रहे हैं, अंकलेश्वर में हो रहे हैं, मेरे पास यह सारा रेकार्ड है । अंकलेश्वर, कपड़वन्ज जो छोटे-छोटे टाउन्ज हैं वहां यह हो रहे हैं । . . . **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: वहां कांग्रेस का एवीडेन्स है और वहां लोगों को पकड़ा गया है । . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Mathur, I have already told him to sit down.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में उठाना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पाण्डेय जी, एक मिनट आप बैठिए : This is the time for Special Mentions and only those who are permitted are entitled to speak. So let us not interrupt. Let the Special Mentions go on.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल के लड़के हितेश पटेल जो अब अहमदाबाद विश्वविद्यालय का छात्र है को इसमें उसे बुरी तरह से मारा गया है और अस्पताल में वह जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और यह बदले की भावना से किया गया है । उस लड़के के प्रति पूरे सदन की सहानुभूति है क्योंकि हमारे एक कुलीग का वह बेटा है और सरकार ऐसी चीजों को न करे । जहां भी वर्तमान सरकार के समर्थक दलों की सरकारें हैं वहीं इस तरह का अत्याचार, अनाचार, दुराचार और हत्याएं हो रही हैं । इसे रोकने का आदेश दें ।

Situation arising out of communal and caste tensions in the country with particular reference to minorities in Assam

श्री असद मदनी- (उत्तर प्रदेश) : वाइस-चैयरमेन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका दिया गया, मुल्क के हालात के मुत्तालिक जो खास तौर पर बहुत खराब चीजें मालूम होती हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ।

अभी जिक्र भी किया गया कि आनंदखेड़ा जिले में परसों दोपहर में लोग मस्जिद में नवाज पढ़ रहे थे तो वहां गणपति के जलूश की जो भीड़ जा रही थी, उन्होंने मस्जिद में घुसकर लोगों पर हमला कर दिया । पुलिस ने साथ होते हुए भी कन्ट्रोल नहीं किया । वह जब काफी मारपीट कर रहे थे तो पुलिस